## खबर एक्सप्रेस

### हड़ताल से पहले आम लोगों की सुविधा के लिए रविवार को खुले रहेंगे बैंक

**नई दिल्ली।** आम लोगों की बैंकिंग जरूरतों में व्यवधान को कम करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार को खुले रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल से एक दिन पहले लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) रविवार को सामान्य रूप से काम करेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए और इससे पहले 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत की छुट्टियां होने के कारण सरकार ने नागरिकों की बैंकिंग जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।" इस कदम से हड़ताल के समय के कारण आर्थिक गतिविधियों में होने वाले व्यवधान को कम करने में मदद मिली है। अगर शनिवार और रविवार दोनों दिन बैंक बंद रहते, तो हड़ताल के कारण बैंकिंग गतिविधियां लगातार पांच दिनों तक प्रभावित होतीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की यूएफबीयू तथा कुछ अन्य यूनियनों ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना वापस लेने की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। फिलहाल बैंक कर्मचारियों को महीने में दो शनिवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन बैंक यूनियनें बाकी दो शनिवार को भी छुट्टी किए जाने की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ग्राहकों का कल्याण और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है। साथ ही, आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है। सरकार का कहना है कि उसने यूनियनों की प्रमुख मांगों में से एक को पहले ही पूरा कर दिया है और पीएलआई योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विस्तृत चर्चा के बाद पीएलआई योजना को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया।

### सरकार ने कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाकर किया शून्य

**नई दिल्ली।** खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे आयात लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को खाद्य तेल की कीमतों में राहत मिल सकेगी। नई शुल्क व्यवस्था के तहत कच्चे सूरजमुखी तेल (क्रूड सनफ्लावर ऑयल) पर लगने वाली 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। वहीं कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम ऑयल पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने साथ ही परिष्कृत (रिफाइंड) खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क में भी कमी की है, लेकिन कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच 19.25 प्रतिशत का शुल्क अंतर बरकरार रखा है। इसका उद्देश्य घरेलू रिफाइनिंग उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से आयात लागत बढ़ी है, जिसका असर घरेलू खुदरा बाजार में भी देखने को मिला है। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में आयात शुल्क उत्पाद की लैंडेड कॉस्ट और अंतिम खुदरा कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के अनुसार, कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती से आयात लागत कम होगी और इसका लाभ पूरी आपूर्ति शृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। यह कदम घरेलू परिवारों पर बढ़ती खाद्य महंगाई का बोझ कम करने और समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच पर्याप्त शुल्क अंतर बना रहे, ताकि तैयार तेल के आयात को बढ़ावा न मिले और देश के रिफाइनिंग उद्योग को नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार, यह नीति घरेलू रिफाइनर्स के लिए समान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करेगी और देश के भीतर वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने शुल्क कटौती के साथ खाद्य तेल उद्योग संगठनों और संबंधित कंपनियों को एक सलाह भी जारी की है। इसमें उनसे आयात शुल्क में कमी का लाभ जल्द से जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की गई है, ताकि बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में वास्तविक राहत दिखाई दे।

**भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 1248 और निफ्टी 384 अंक गिरा**

# निवेशकों की वेल्थ 4 लाख करोड़ रुपए घटी

- अमेरिकी बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज मिलना, महंगा कच्चा तेल भी गिरावट की मुख्य वजह बने

आज समाज नेटवर्क




**नई दिल्ली।** शेयर बाजार में आज यानी 24 सितंबर को गिरावट रही। सेंसेक्स 1248 अंक या 1.67% गिरकर 73,581 पर बंद हुआ।

निफ्टी में भी 384 अंक या 1.64% की गिरावट रही। ये 23,063 पर आ गया। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। ब्रेंट क्रूड करीब 102 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।

ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता से तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर है। महंगा तेल भारत के लिए चिंता है, क्योंकि इससे तेल आयात का खर्च, महंगाई और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ना निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है। 10-साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 5.11% पर पहुंच गई है जो 2007 के बाद का उच्चतम स्तर है। बॉन्ड यील्ड किसी सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला सालाना रिटर्न है, जिसे कोई एक संस्था या सरकार सीधे तय नहीं करती, बल्कि यह बाजार में खरीद-बिक्री और मांग-आपूर्ति से तय होती है। जब निवेशक बॉन्ड बेचते हैं तो बॉन्ड की कीमत घटती है और यील्ड (रिटर्न) बढ़ जाती है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां और महंगाई इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं।

इस यील्ड के बढ़ने से डॉलर में निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाता है, जिससे विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं। IRDAI के प्रस्तावित बदलावों से इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई घट सकती है। इसका असर इंश्योरेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर दिखा। इंश्योरेंस कंपनी PB फिनटेक करीब 10% तक गिर गया, जबकि एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी दबाव में रहे। भारतीय शेयर बाजार में आई तेज बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ 3.94 लाख करोड़ रुपए घट गई है। कल जब बाजार बंद हुआ था, तब इए में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 485 लाख करोड़ रुपए थे, जो आज घटकर 481 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। पैनिक सेलिंग से बचें: बाजार का गिरना और उठना सामान्य बात है। घबराहट में आकर सस्ते दाम पर शेयर बेचने से आपको बड़ा घाटा हो सकता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें: गिरावट के समय अपने निवेश को दोबारा सेट करें। इस दौरान मजबूत फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका मिल सकता है।

लंबी अवधि का नजरिया रखें: बाजार के शॉर्ट टर्म उतार-चढ़ाव पर ध्यान न देकर अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर टिके रहें। जो निवेशक लंबे समय तक टिके रहते हैं, वे बेहतर रिटर्न कमाते हैं। ए-वन स्टील्स और मनीव्यू के IPO आज से ओपन हो गए हैं। निवेशक इनमें 28 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। ए-वन स्टील्स इस IPO के जरिए 405 करोड़ रुपए और मनीव्यू 1,091.68 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।

# आज से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो

- पांच दिन चलने वाले ट्रेड शो से राज्य में बड़े निवेश की उम्मीद

आज समाज नेटवर्क




**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में होने वाले UP Internatiobal Trade Show 2026 (UPITS) में इस बार 6 देशों की कंपनियां और बिजनेस डेलिगेशन शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का मकसद उत्तर प्रदेश की कंपनियों को विदेशी बाजारों से जोड़ना और व्यापार व निवेश के नए मौके तलाशना है। UPITS 2026 का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जाएगा। इस बार वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल होंगे। ट्रेड शो में अलग-अलग देशों के पवेलियन बनाए जाएंगे। यहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट, नई तकनीक और निवेश के अवसरों की जानकारी देंगी। इसके अलावा B2B मीटिंग, देश-विशेष सेशन और फॉरेन डेलिगेशन की उत्तर प्रदेश के कारोबारियों के साथ बैठकें होंगी। वियतनाम और जापान को 54-54 वर्ग मीटर जगह दी गई है। सिंगापुर और रूस के लिए 36-36 वर्ग मीटर और ऑस्ट्रिया के लिए 54 वर्ग मीटर जगह तय की गई है। इन 5 देशों से करीब 36 प्रदर्शक और 100 खरीदार शामिल होने की योजना है। बेलारूस भी पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा और वहां से वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि B2B एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को फॉरेन डेलिगेशन की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी होगी। इसमें राजदूत, हाई कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव और वरिष्ठ कारोबारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। वियतनाम की कंपनियां एविएशन, टूरिज्म, कृषि, फार्मास्युटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फूड, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में हिस्सा लेंगी। जापान पवेलियन में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। इनमें Wacom India, Air and Water India, ITO EN, Sushi and More, Kito India और Taiyo India शामिल हैं।

# एक्सप्रेसवे और फास्ट ट्रेनों से आसान हो रहा सफर

- घट गया कई शहरों का ट्रैवल टाइम

आज समाज नेटवर्क



**नई दिल्ली।** भारत में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और तेज रफ्तार ट्रेनों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। इससे देश के कई बड़े शहरों के बीच ट्रैवल टाइम घट गया है। कई जगहों पर नई सड़क और रेल प्रोजेक्ट्स ने लंबे रास्तों, नदियों और पहाड़ी इलाकों की मुश्किलों को कम किया है। दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-कटरा और जम्मू-श्रीनगर जैसे रूट इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच ट्रैवल टाइम करीब 33 घंटे से घटकर लगभग 12 घंटे होने का अनुमान है। वहीं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम करीब 2.5 घंटे से घटकर लगभग 50 मिनट हो गया है। 82 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को तेज किया है। बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे ने भी यात्रा का समय करीब तीन घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर दिया है। वहीं दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से सफर 6 घंटे से ज्यादा से घटकर करीब 2.5 घंटे रह गया है। मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग से दोनों शहरों के बीच यात्रा करीब 16 घंटे से घटकर लगभग आठ घंटे रह गई है। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद-धोलेरा का सफर करीब 2 घंटे 15 मिनट से घटकर 45 मिनट रह गया है। इसी तरह अहमदाबाद-भावनगर यात्रा करीब 3 घंटे 15 मिनट से घटकर 1 घंटे 45 मिनट हो गई है। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पहले चरण से दिल्ली-अमृतसर यात्रा करीब 8 घंटे से घटकर चार घंटे और दिल्ली-कटरा यात्रा 14 घंटे से घटकर करीब छह घंटे रह गई है। नदियों और पहाड़ी इलाकों वाले नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पुलों ने यात्रा को काफी आसान किया है। भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला-सादिया ब्रिज से असम के रुपाई और अरुणाचल प्रदेश के मेका/रोइंग के बीच यात्रा करीब 6 घंटे से घटकर एक घंटे रह गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील ब्रिज से धीमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच यात्रा, जो पहले लगभग पूरा दिन लेती थी, अब करीब एक से दो घंटे में हो जाती है। बिहार में कोसी रेल महासेतु ने निर्मली और सरायगढ़ के बीच रेल यात्रा को करीब आठ घंटे से घटाकर सिर्फ 30 मिनट कर दिया। इस रूट की रेल दूरी भी करीब 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर रह गई है।

पहाड़ी इलाकों में सुरंगों ने लंबे और मुश्किल रास्तों को छोटा किया है। हिमाचल प्रदेश की 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग दर्रे को बायपास करती है। इससे मनाली-सरचू दूरी 46 किलोमीटर कम हुई है और करीब 4-5 घंटे का समय बचता है। जम्मू-कश्मीर में डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से जम्मू-श्रीनगर रूट की सड़क दूरी करीब 30 किलोमीटर कम हुई है और लगभग दो घंटे का समय बचता है। वहीं बनिहाल-काजीगुंड ट्विन-ट्यूब टनल से करीब 1।5 घंटे की बचत होती है। अरुणाचल प्रदेश की करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल ने तेजपुर-तवांग रूट पर यात्रा का समय एक घंटे से ज्यादा कम किया है और हर मौसम में कनेक्टिविटी देने में मदद की है। रेलवे में भी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। 2026 की रेलवे टाइमटेबल व्यवस्था में 549 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई गई। इनमें 20 ट्रेनों के सफर का समय एक घंटे या उससे ज्यादा कम हुआ, जबकि 48 ट्रेनों के समय में 31 से 59 मिनट की कमी हुई। नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत करीब 8 घंटे में सफर पूरा करती है। यह पहले की सेवाओं की तुलना में करीब 40-50 फीसदी तेज है।एक्सप्रेस कटरा-श्रीनगर वंदे भारत से यात्रा करीब तीन घंटे में पूरी हो रही है। जम्मू-श्रीनगर रूट पर विस्तारित सेवा करीब 4 घंटे 50 मिनट में सफर पूरा करती है। बनारस-खजुराहो सेवा से करीब 2 घंटे 40 मिनट और एनार्कुलम-बेंगलुरु सेवा से दो घंटे से ज्यादा समय बचता है। हावड़ा-गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर सेवा ने यात्रा का समय करीब 17 घंटे से घटाकर लगभग 14 घंटे कर दिया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से भी यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 320kmph होगी। इसके जरिए मुंबई-अहमदाबाद यात्रा करीब 1 घंटे 58 मिनट में पूरी करने का लक्ष्य है, जबकि सड़क से इसमें करीब 8-9 घंटे लगते हैं।

# आने वाले दिनों में सुधर सकती है रुपए की हालत

- पिछले डेढ़ साल में डॉलर के मुकाबले 13 प्रतिशत से ज्यादा कमजोर हुई भारतीय करेंसी

आज समाज नेटवर्क



**मुंबई।** भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा है कि रुपये के मौजूदा स्तर से सिर्फ स्थिर होने ही नहीं, बल्कि मजबूत होने की भी गुंजाइश है। उनका कहना है कि पिछले करीब डेढ़ साल में रुपये में आई 13.1 फीसदी की गिरावट अस्थायी घटना हो सकती है।

गुप्ता ने बुधवार को मुंबई में 13वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही। पूनम गुप्ता ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2025 से 16 सितंबर 2026 के बीच रुपये में 13.1 फीसदी की संचयी गिरावट आई है। गुप्ता के मुताबिक, इसे रुपये का जरूरत से ज्यादा कमजोर होना यानी 'ओवरकरेक्शन' भी माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूंजी प्रवाह से जुड़े उपायों की घोषणा के समय बाजार विश्लेषक भी रुपये में मजबूती की उम्मीद कर रहे थे।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वित्त वर्षों में नकारात्मक रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 5 अरब डॉलर और 2025-26 में 23.6 अरब डॉलर का नकारात्मक भुगतान संतुलन दर्ज किया गया। इसकी एक वजह यह रही कि पूंजी खाते का अधिशेष चालू खाते के घाटे से कम रहा। आने वाले वर्षों में भारत का चालू खाता घाटा और कम होने की उम्मीद है। सेवाओं का निर्यात और विदेशों से आने वाला पैसा भारत की मजबूत पारंपरिक ताकत बने हुए हैं। वस्तुओं के निर्यात में बढ़ती सफलता भारत की नई ताकत के तौर पर उभर रही है। हाल के मुक्त व्यापार समझौतों का सकारात्मक असर और अनुकूल विनिमय दर भी निर्यात को सहारा दे सकती है। पूनम गुप्ता ने कहा कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता आने वाले समय में कम हो सकती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल और देश में अपने तेल भंडार खोजने के प्रयासों से जीडीपी के मुकाबले तेल की मांग में कमी आने की उम्मीद है। इससे भारत के बाहरी खाते पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि, हाल में तेल और सोने की कीमतों में आए झटकों ने चालू खाता घाटे को अस्थायी रूप से बढ़ाया है।

गुप्ता के मुताबिक, सेवाओं का शुद्ध निर्यात और विदेशों से आने वाला पैसा इतना बड़ा और मजबूत स्रोत है कि वह वस्तुओं के व्यापार घाटे को संभाल सकता है और चालू खाता घाटे को जीडीपी के एक फीसदी से नीचे रख सकता है। डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि पूंजी खाते की स्थिति मौजूदा वित्त वर्ष के बाद के हिस्से में ज्यादा अनुकूल हो सकती है। उन्होंने इसके लिए भारत के मजबूत घरेलू आर्थिक आधार, वास्तविक और नाममात्र जीडीपी की ऊंची वृद्धि, घरेलू निवेश चक्र और बैंकों व कंपनियों की स्वस्थ बैलेंस शीट को अहम वजह बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे बाजारों में ऊंचे मूल्यांकन और एआई आधारित निवेश में संतृप्ति भारत के लिए पूंजी आकर्षित करने का अवसर बन सकती है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में बढ़ोतरी भी पूंजी प्रवाह को सहारा दे सकती है। भारतीय बॉन्ड के आगे चलकर ज्यादा वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। गुप्ता ने कहा कि जून में लागू किए गए विशेष पूंजी प्रवाह उपायों से इस साल भारत को महत्वपूर्ण भुगतान संतुलन अधिशेष मिला है।

यह दिखाता है कि भारत बहुत कम 'कंट्री प्रीमियम' पर बड़े पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित परिस्थितियां बनाए रखने के लिए आरबीआई प्रतिबद्ध है और उसके पास भारत के चालू खाता घाटे या शुद्ध भुगतान संतुलन घाटे की जरूरतों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

गुप्ता ने कहा कि भारत का चालू खाता घाटा समय के साथ कम हुआ है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आम तौर पर उचित माने जाने वाले स्तर से काफी नीचे बना हुआ है।

# अदाणी स्मूह पश्चिम बंगाल में करेगा एक लाख करोड़ रुपए का निवेश

- समूह ने 2035 तक की निवेश रूपरेखा की तैयार

आज समाज नेटवर्क



**कोलकाता।** अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की। यह निवेश प्रस्तावित अदाणी आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा परियोजना में होगा। इस परियोजना से 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अडानी ने बताया कि समूह 2035 तक पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश करेगा। अदाणी ने न्यू टाउन में परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान यह घोषणा की। अदाणी आरोग्य मंदिर 2,000 बिस्तरों वाला एक गैर-लाभकारी चिकित्सा संस्थान होगा। इसमें से 1,000 बिस्तर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। ये बिस्तर राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पात्र लोगों को मिलेंगे।

इस सुविधा में एक मेडिकल कॉलेज और उन्नत शोध व स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं भी शामिल होंगी। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी और बेटे करण अडानी के साथ 'भूमि पूजन' किया। अदाणी समूह का लक्ष्य 2035 तक पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना है। यह निवेश पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण जैसे क्षेत्रों में होगा। इसके अतिरिक्त, सड़क, पुल, रोपवे, ग्रीन सीमेंट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर भी शामिल हैं। समूह ने कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए भी समर्थन की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के औद्योगिक केंद्र, पूर्वोत्तर और बे ऑफ बंगाल के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री और लॉजिस्टिक्स कड़ी बनाती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार अदाणी समूह के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया आकार देना है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने अदाणी से राज्य में निवेश का अनुरोध किया था। अदाणी समूह ने कुछ ही महीनों में इस स्वास्थ्य सेवा परियोजना की घोषणा करके जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अदाणी से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद का आग्रह किया है। अधिकारी ने कहा कि यह अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अपनी आधी बिस्तर क्षमता मुफ्त में आरक्षित रखेगा।

**वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 की आधिकारिक तैयारियां की शुरू**

# प्री बजट की मीटिंग्स 12 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेंगी

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 10वां बजट होगा

आज समाज नेटवर्क



**नई दिल्ली।** वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 की आधिकारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में 12 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलने वाली महीने भर की प्री-बजट बैठकों (Pre-Budget Meetings) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Departmebt of Expenditure) के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य चालू वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमानों (RE) और अगले वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों (BE) को अंतिम रूप देना है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने आवश्यक वित्तीय आंकड़े और खर्च के प्रस्ताव 6 अक्टूबर तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार सरकार का मुख्य ध्यान फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने, गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue) बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं के तर्कसंगत आबंटन पर रहेगा।

1 फरवरी 2027 को पेश होने वाला यह बजट मोदी 3.0 सरकार का चौथा और वित्त मंत्री का लगातार 10वां बजट होगा, जो देश की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अनुशासन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्रालय 2027-28 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत 12 अक्टूबर से एक महीने तक बजट-पूर्व बैठकें शुरू करेगा।

मंत्रालय के बजट विभाग ने 23 सितंबर को जारी एक नोटिस में कहा कि अनुदान और विनियोग के संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा 12 अक्टूबर से व्यय सचिव की अध्यक्षता में शुरू होगी। यह सूचना सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है।

इसमें व्यय विभाग के साथ होने वाली बैठकों का कार्यक्रम दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे काफी पहले जारी किया जा रहा है। सूचना के अनुसार, मंत्रालयों और विभागों को बैठकों के लिए जरूरी जानकारी छह अक्टूबर, 2026 तक जमा करनी होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बैठकें 13 नवंबर तक चलेंगी। बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्त वर्ष 2027-28 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार दसवां बजट होगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिए जाने की उम्मीद है।

**MANAPPURAM FINANCE LTD.**

CIN: L65910KL1992PLC006623,
**Registered Office :** W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

**निलामी सूचना**

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.10.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भिवानी, भिवानी, 0119170700037455, 7622, 8303, 8332, 8342, 8351, 8352, 8355, 8372, 8373, 8379, 8383, 8504, 0119170730035958, 5962, 5963, 5964, 5972, 5977, 5987, 5990, 5998, 6010, 6016, 6017, 6031, 6037, 6038, 6058, 6059, 6089, चरखी दादरी, 0138050700004060, 4065, 0138050730007022, 7556, 7757, दीनोद गेट भिवानी, 0138570700005827, 5855, 5861, 5862, 5864, 0138570730008174, 0183, 0271, 0272, 0274, 0279, 0281, 0282, 0286, 0287, 0288, 0307, 0312, 0323, 0338, फ़तेहाबाद, फ़तेहाबाद, 0129250700035999, 6015, 6036, 6042, 6598, 6633, 0129250730017885, 9400, 9430, 9441, 9449, 9460, 9461, 9466, 9507, 9508, 9535, 9536, 9537, टोहाना फतेहाबाद, 0129690700025972, 6545, 6713, 6715, 6717, 6725, 6797, 6802, 7428, 7449, 7470, 7474, 7476, 7479, 7502, 7504, 7524, 7530, 7540, 7542, 7544, 7546, 0129690730033696, 3723, 3778, 3821, 5698, 5748, 5758, 5821, 5832, 5858, 5869, 5870, 5874, 5892, 5898, 5909, 5911, 5912, 5955, 5958, 0087, हिसार, हांसी हिसार, 0131230700027052, 7455, 7460, 7461, 7487, 7508, 7541, 8239, 8258, 8315, 8341, 8347, 8371, 8372, 8375, 8377, 8379, 8390, 8396, 8407, 8414, 8417, 8420, 8438, 0131230730021265, 2384, 3411, 4400, 5045, 5055, 5128, 5210, 8945, 8970, 8972, 9017, 9023, 9077, 9090, 9095, 9100, 9113, 9122, 9179, 9204, 9218, 9223, 9230, 9241, 9248, 9270, 0183, 0185, रेड स्क्वेयर मार्केट, 0123360700037553, 7690, 7976, 8024, 8049, 8706, 8712, 8731, 8739, 8741, 8743, 8772, 0123360730052824, 6922, 6950, 7018, 7037, 7108, 7116, 7122, 7164, 7165, 7166, 7177, 7178, 7191, 7192, 7199, 7203, 7225, 7228, 7239, 7240, 7249, 7256, हिसार, हिसार, 0118710700032400, 4543, 4753, 4967, 6007, 6257, 6322, 6466, 6480, 6499, 6505, 6509, 7248, 7281, 7348, 7354, 7371, 7382, 7394, 7408, 7409, 7423, 0118710730031339, 1406, 5205, 5309, 5471, 5484, 5514, 5530, 5532, 5560, 5561, 5583, 5596, 5600, 5601, 5610, 5612, 5621, 5627, 5638, 5644, जींद, भगवान नगर जीं